

योजना पत्रिका का सारांश

जुलाई 2026



विकसित भारत @ 2047

विषय 1: सांस्कृतिक विरासत और भारत का सभ्यतागत पुनरुत्थान (CULTURAL HERITAGE AND INDIA'S CIVILISATIONAL RENAISSANCE)

सभ्यतागत पुनरुत्थान, विकास भी विरासत भी, पंच प्रण, नए संसद भवन के प्रतीकात्मक द्वार, सेंगोल की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, ज्ञान भारतम मिशन, मेरा गांव मेरी धरोहर, और सांस्कृतिक कूटनीति (लेखक: डॉ. सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, IGNCA)

सभ्यतागत पुनरुत्थान विजन: “समकालीन भारत सभी प्राचीन सभ्यताओं के सामने आने वाले एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा है: क्या कोई सभ्यता अपने अतीत को बिना उसमें फंसे पुनः प्राप्त कर सकती है, और क्या कोई आधुनिक देश बिना यह भूलें आगे बढ़ सकता है कि वह कौन है?” — डॉ. सच्चिदानंद जोशी

1. कार्यकारी सारांश एवं सभ्यतागत पुनरुत्थान की अवधारणा

जुलाई 2026 के ‘योजना’ अंक (विषय: विकसित भारत @ 2047: प्रौद्योगिकी और संघर्षशीलता) के पहले आलेख ‘सांस्कृतिक विरासत और भारत का सभ्यतागत पुनरुत्थान’ (Cultural Heritage and India's Civilisational Renaissance) में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के सदस्य सचिव और भारतीय विरासत संस्थान के वाइस चांसलर डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने विश्लेषण किया है कि कैसे पिछले एक दशक में भारत ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ एक नए जुड़ाव (सभ्यतागत पुनरुत्थान) का अनुभव किया है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकास भी, विरासत भी’ के दृष्टिकोण के तहत आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण को परस्पर विरोधी मानने के बजाय एकीकृत किया गया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में घोषित ‘पंच प्रण’ (विशेषकर भारत की विरासत पर गर्व करना और औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति) ने इस सांस्कृतिक नीति को वैचारिक आधार प्रदान किया है।

2. सार्वजनिक वास्तुकला और प्रतीकों में परंपरा का प्रतिबिंब

- नए संसद भवन के द्वार:** नए संसद भवन के छह औपचारिक द्वारों (गज-द्वार, अश्व-द्वार, गरुड़-द्वार, हंस-द्वार, मकर-द्वार और शार्दूल-द्वार) को भारतीय परंपराओं से जुड़ी बलुआ पत्थर की मूर्तियों से सजाया गया है, जो ज्ञान, शक्ति और सफलता का प्रतीक हैं।
- सेंगोल की स्थापना:** चोल राजवंश की परंपरा से जुड़े ‘सेंगोल’ को नए संसद

भवन में स्थापित करके न्याय, धर्म और अधिकार के न्यायसंगत हस्तांतरण के सभ्यतागत आदर्श को पुनर्जीवित किया गया है।

- कर्तव्य पथ और सेवा तीर्थ:** राजपथ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ करना औपनिवेशिक सत्ता के स्थान पर भारतीय कर्तव्य के भाव को दर्शाता है।

3. ज्ञान परंपराओं, शिक्षा और जीवित विरासत का संरक्षण

- नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार:** वैश्विक शिक्षण केंद्र के रूप में नालंदा का पुनरुद्धार भारत की बौद्धिक और संवाद परंपरा की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।
- ज्ञान भारतम मिशन (Gyan Bharatam Mission):** देश भर में बिखरे लाखों प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित, कैटालॉग और प्रसारित करने की पहल।
- मेरा गांव मेरी धरोहर (Mera Gaon Meri Dharohar):** राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत गांवों और समुदायों के सांस्कृतिक प्रोफाइल का दस्तावेजीकरण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अभ्यास।

4. कलाकृतियों की वापसी, यूनेस्को मान्यता और सांस्कृतिक कूटनीति

- पुरावशेषों की वापसी (Repatriation):** श्रीपुरम नटराज मूर्ति, मां अन्नपूर्णा देवी और ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्रों सहित 600 से अधिक चुराई गई प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है, जो सांस्कृतिक स्मृति की बहाली का प्रतीक हैं।
- यूनेस्को (UNESCO) मान्यता:** दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करना तथा भगवद्गीता और भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’ में स्थान मिलना भारत की वैश्विक बौद्धिक विरासत को मान्यता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मंच:** भारत मंडपम में स्थापित 27 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक प्रसार ने भारत की सॉफ्ट पावर और सभ्यतागत दर्शन को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: सभ्यतागत पुनरुत्थान के आयाम और पहलें

नीचे दी गई तालिका भारत के सभ्यतागत पुनरुत्थान के प्रमुख क्षेत्रों, पहलों और उनके राष्ट्रीय प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

पुनरुत्थान आयाम	प्रमुख पहल / संस्था	कार्यान्वयन और पैमाना	सभ्यतागत व राष्ट्रीय प्रभाव
वास्तुकला और प्रतीक	नया संसद भवन (द्वार, कलाकृतियां) और सेंगोल की स्थापना	लोकतांत्रिक संस्थाओं को धर्म, न्याय और प्राचीन परंपराओं से जोड़ना	औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की बहाली
ज्ञान परंपराएं और शिक्षा	नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, ज्ञान भारतम मिशन और NEP 2020	पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) का समावेशन	वैश्विक शिक्षण केंद्र के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका की पुनः स्थापना
जीवित विरासत और मानचित्रण	राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन और ‘मेरा गांव मेरी धरोहर’	देश के गांवों और समुदायों के सांस्कृतिक प्रोफाइल का दस्तावेजीकरण	स्थानीय परंपराओं की रक्षा और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा
सांस्कृतिक कूटनीति	600+ चुराए गए पुरावशेषों की वापसी और यूनेस्को (UNESCO) मान्यताएं	अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय दर्शन, योग और ग्रंथों का वैश्विक प्रकटीकरण	भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक विरासत का वैश्विक सम्मान

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख भारतीय कला एवं संस्कृति, इतिहास और राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र I & II (भारतीय संस्कृति — प्राचीन से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला; शासन व्यवस्था — सांस्कृतिक नीतियां और राष्ट्रीय पहचान)

- सभ्यतागत पुनरुत्थान और विकास:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे भारत 'विकास भी, विरासत भी' के सिद्धांत के तहत आधुनिक आर्थिक प्रगति और अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है।
- सांस्कृतिक कूटनीति और पुरावशेषों की वापसी:** ऐतिहासिक कलाकृतियों के प्रत्यावर्तन (repatriation) और यूनेस्को की सूचियों में भारतीय धरोहरों के समावेश के माध्यम से भारत की 'सॉफ्ट पावर' के विस्तार को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा सभ्यतागत दृष्टिकोण: “अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत् प्रयत्नतः, रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पातेषु निक्षिपेत् — जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, जो सुरक्षित है उसे संवर्धित करना और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए उसे सौंपना ही भारत का सभ्यतागत दृष्टिकोण है।” — महासुभाषित संग्रह

विषय 2: भारत का लॉजिस्टिक्स भविष्य: विजन 2047 (INDIA'S LOGISTICS FUTURE: VISION 2047)

परिवहन और लॉजिस्टिक्स, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP 2022), ULIP, LDB, एआई और डेटा साइंस, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, और मल्टीमॉडल परिवहन योजना (लेखक: प्रो. मनोज चौधरी, कुलपति, गति शक्ति विश्वविद्यालय)

लॉजिस्टिक्स विजन: “परिवहन और लॉजिस्टिक्स किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। जितनी मजबूत लॉजिस्टिक्स सेवाएं होंगी, हमारे बॉर्डर उतने ही सुरक्षित रहेंगे। लॉजिस्टिक्स का GDP ग्रोथ पर मल्टीप्लायर प्रभाव होता है।” — प्रो. मनोज चौधरी

1. कार्यकारी सारांश एवं लॉजिस्टिक्स का रणनीतिक महत्व

जुलाई 2026 के 'योजना' अंक के दूसरे आलेख 'भारत का लॉजिस्टिक्स भविष्य: विजन 2047' (India's Logistics Future: Vision 2047) में गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज चौधरी ने विश्लेषण किया है कि कैसे पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अपनी आर्थिक परिवर्तन यात्रा के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए भी कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणालियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। महामारी और वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों (जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट) ने लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं (resilient supply chains) की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

2. बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण (Infrastructure at Scale)

- भारतीय रेलवे:** ब्रॉड-गेज नेटवर्क का लगभग 100% विद्युतीकरण, वंदे

भारत और अमृत भारत स्टेशन पुनरुद्धार, कवच सुरक्षा तकनीक, और माल ढुलाई राजस्व (Freight Revenue) में 90% की वृद्धि (₹93,400 करोड़ से बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़)।

- समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (DFC):** पूर्वी और पश्चिमी DFC के 2,843 किमी का निर्माण, जिससे मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों का पृथक्करण संभव हुआ है।
- राजमार्ग और एक्सप्रेसवे:** भारतमाला (22,500+ किमी), कुल राजमार्ग नेटवर्क का 1.46 लाख किमी तक विस्तार, और गंगा एक्सप्रेसवे व दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जैसे एक्ससेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे।
- बंदरगाह और जलमार्ग:** अंतर्देशीय जलमार्गों पर कार्गो संचलन में 700% की भारी वृद्धि (18.1 MMT से बढ़कर 145.5 MMT), राष्ट्रीय जलमार्गों का 5 से 111 तक विस्तार, और 9 भारतीय बंदरगाहों का दुनिया के शीर्ष 100 में शामिल होना।
- नागर विमानन और शहरी गतिशीलता:** हवाई अड्डों की संख्या 74 (2014) से बढ़कर 165 (2026) होना, UDAN योजना, तथा 26 शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार (1,155 किमी)।

3. नीतिगत ढांचा: पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

- पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (2021):** भू-स्थानिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए 'होल ऑफ द गवर्नमेंट' दृष्टिकोण के तहत 58 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 3,200+ डेटा लेयर्स को एकीकृत करना। इसके तहत 4 वर्षों में ₹15 लाख करोड़ के 240 प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन किया गया है।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP 2022):** डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणालियों का एकीकरण, भौतिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण, और ई-सिम (EXIM) लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म (ULIP और LDB):** यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) विभिन्न सरकारी प्रणालियों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है, जबकि लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) RFID और IoT के माध्यम से EXIM कंटेनरों की 100% ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है।

4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा साइंस की भूमिका

- बुद्धिमान परिवहन प्रणालियां (ITS):** FASTag के माध्यम से टोल संग्रह का डिजिटलीकरण, और AI-सक्षम ट्रैफिक सिग्नल नियंत्रण प्रणाली।
- पूर्वानुमानित रखरखाव (Predictive Maintenance):** रेलवे, विमानन और राजमार्गों पर सेंसर और जीपीएस डेटा का विश्लेषण करके घटकों की खराबी का पहले ही पता लगाना, जिससे डाउनटाइम और जीवनचक्र लागत कम होती है।
- वेयरहाउसिंग का आधुनिकीकरण:** डिजिटल द्विन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और रोबोटिक्स के उपयोग से तापमान-नियंत्रित और खतरनाक कार्गो वेयरहाउसिंग में दक्षता।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: लॉजिस्टिक्स आयाम, बुनियादी ढांचा और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रमुख घटकों, तकनीकी पहलुओं और उनके आर्थिक प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

लॉजिस्टिक्स आयाम	प्रमुख नीति / ढांचा	परिचालन पैमाना व मेट्रिक्स	आर्थिक व रणनीतिक प्रभाव
बुनियादी ढांचा आधुनिकीकरण	रेलवे (100% विद्युतीकरण), DFC, राजमार्ग और जलमार्ग	माल ढुलाई आय बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़; जलमार्ग कार्गो 145.5 MMT	परिवहन लागत में कमी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती
शासन और डिजिटल योजना	पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)	3,200+ डेटा लेयर्स और 58 केंद्रीय मंत्रालयों का एकीकरण	डेटा-संचालित निर्णय, साइलो की समाप्ति और तीव्र परियोजना क्रियान्वयन
डिजिटल गेटवे और ट्रेकिंग	ULIP (यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म) और LDB	RFID और IoT के माध्यम से EXIM कंटेनरों की 100% ट्रेकिंग	दस्तावेज़ डिजिटलीकरण, प्रक्रिया स्वचालन और पारदर्शी दृश्यता
उभरती तकनीकें (AI & ITS)	इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, FASTag और प्रेडिक्टिव मटेनेंस	रियल-टाइम डेटा विश्लेषण, रूट ऑप्टिमाइज़ेशन और ड्रोन डिलीवरी	उच्च दक्षता, कम डाउनटाइम और सुरक्षित हाई-स्पीड गतिशीलता

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास और आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (बुनियादी ढांचा — ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे, विमानन; निवेश मॉडल और आर्थिक विकास)

- पीएम गति शक्ति और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) ने अंतर-मंत्रालयी साइलो को तोड़कर देश में बुनियादी ढांचे के विकास और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को गति दी है।
- प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन:** AI, IoT और डिजिटल प्लेटफॉर्म (ULIP) के उपयोग के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा लॉजिस्टिक्स दृष्टिकोण: “लॉजिस्टिक्स दक्षता का माप इस बात से है कि पहली और अंतिम मील की कनेक्टिविटी कितनी सहज है, आपूर्ति श्रृंखलाएं कितनी लचीली हैं, और माल की आवाजाही कितनी पूर्वानुमानित है। विकसित भारत 2047 के लिए एकीकृत परिवहन योजना अत्यंत आवश्यक है।” — प्रो. मनोज चौधरी

विषय 3: उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक फ्रेमवर्क (LONG-TERM STRATEGIC FRAMEWORK FOR AT-MANIRBHARTA IN FERTILISER)

रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE), कोयला गैसीकरण मिशन, ग्रीन अमोनिया, नैनो उर्वरक (नैनो यूरिया और नैनो DAP), प्राकृतिक खेती, साइल हेल्थ कार्ड, फसल विविधीकरण, और एग्री स्टैक (लेखक: डॉ. देवेश चतुर्वेदी, पूर्व सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)

उर्वरक आत्मनिर्भरता विजन: “वर्तमान पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, प्रधानमंत्री ने रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग और प्राकृतिक खेती को अपनाने सहित सात सूत्रीय अपील जारी की है। दीर्घकालिक संधारणीय कृषि के लिए उर्वरक उपलब्धता में आत्मनिर्भरता अत्यंत महत्वपूर्ण है।” — डॉ. देवेश चतुर्वेदी

1. कार्यकारी सारांश एवं कृषि क्षेत्र की चुनौतियां

जुलाई 2026 के ‘योजना’ अंक के तीसरे आलेख ‘उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक फ्रेमवर्क’ (Long-term Strategic Framework for Atmanirbharta in Fertiliser) में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने विश्लेषण किया है कि कैसे भारतीय कृषि ने पिछले एक दशक में 4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों (जैसे पश्चिम एशिया संकट) के कारण उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक बड़ी नीतिगत प्राथमिकता बन गई है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) में क्रमिक गिरावट के कारण किसानों को समान उत्पादकता बनाए रखने के लिए लगातार अधिक उर्वरक डालना पड़ रहा है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, यूरिया और DAP की कीमतों पर सरकारी सब्सिडी का भारी वित्तीय बोझ वैश्विक तेल और गैस की कीमतों के उतार-चढ़ाव से जुड़ा हुआ है।

2. आत्मनिर्भरता के लिए तीन प्रमुख रणनीतिक स्तंभ

- गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विकल्प:** नाइट्रोजन और अन्य उर्वरकों के निर्माण के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित वैकल्पिक स्रोतों का विकास (जैसे कोयला गैसीकरण और ग्रीन अमोनिया)।
- स्वदेशी उत्पाद:** ऐसे स्वदेशी उत्पादों का विकास और अपनाना जिनकी प्रभावशीलता लोकप्रिय रासायनिक उर्वरकों के समान हो (जैसे नैनो उर्वरक)।
- मांग में कमी और संतुलित उपयोग:** मृदा स्वास्थ्य में सुधार करते हुए संधारणीय और जलवायु-अनुकूल उत्पादन के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग की ओर बढ़ना।

3. तकनीकी नवाचार और वैकल्पिक उर्वरक स्रोत

- राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन:** देश में प्रचुर कोयला भंडार का उपयोग करते हुए, सरकार ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹37,500 करोड़ के परिव्यय के साथ सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे पेट्रोलियम गैस के बिना अमोनिया का उत्पादन संभव होगा।
- ग्रीन अमोनिया (Green Ammonia):** नाइट्रोजन का समृद्ध स्रोत (लगभग 82%), जिसके उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। ICAR के साथ निजी क्षेत्र इसके क्षेत्र परीक्षण (field trials) कर रहा है।
- नैनो उर्वरक (Nano Fertilisers):** नैनो यूरिया और नैनो DAP ने पारंपरिक यूरिया और DAP को आंशिक रूप से बदलने की क्षमता दिखाई है। ICAR के ढांचे के तहत फसल-वार खुराक और समय के लिए मजबूत परीक्षण जारी हैं।

4. मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती और एग्री स्टैक (Agri Stack)

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** किसानों को 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए हैं, जिन्हें अब एकीकृत पोषण प्रबंधन (INM) के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
- प्राकृतिक खेती:** राष्ट्रीय प्राकृतिक मिशन के तहत गाय-आधारित और क्षेत्र-विशिष्ट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो।
- एग्री स्टैक (Digital Public Infrastructure):** डिजिटल कृषि मिशन के तहत 9.5 करोड़ से अधिक किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं

रणनीतिक आयाम	प्रमुख तकनीक / नीतिगत पहल	कार्यान्वयन और पैमाना	दीर्घकालिक प्रभाव व लाभ
कोयला गैसीकरण	राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन और ₹37,500 करोड़ की योजना	2030 तक 100 MT कोयला गैसीकरण का लक्ष्य	पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू अमोनिया उत्पादन
ग्रीन अमोनिया	जीवाश्म ईंधन-मुक्त अमोनिया उत्पादन और ICAR फील्ड परीक्षण	निजी क्षेत्र और ICAR द्वारा विभिन्न मिट्टी पर परीक्षण जारी	पर्यावरण-अनुकूल नाइट्रोजन आपूर्ति और कृषि में शून्य-कार्बन इनपुट
नैनो उर्वरक	नैनो यूरिया और नैनो DAP का विकास और मानकीकृत अनुप्रयोग	पिछले 5 वर्षों में व्यापक विस्तार और वैज्ञानिक परीक्षण	पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों की खपत में आंशिक कमी और बेहतर पोषक तत्व दक्षता
डिजिटल शासन (Agri Stack)	किसान आईडी रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (30 करोड़+ प्लॉट)	24 राज्यों के 640+ जिलों में डिजिटल सर्वेक्षण	उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, संतुलित खुराक की सलाह और लीकेज की रोकथाम

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख कृषि, खाद्य सुरक्षा, उर्वरक नीति और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (कृषि — प्रौद्योगिकी मिशन, उर्वरक सब्सिडी, मृदा स्वास्थ्य, और खाद्य सुरक्षा व आत्मनिर्भरता)

- उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे भारत कोयला गैसीकरण, ग्रीन अमोनिया और नैनो उर्वरकों जैसी वैकल्पिक तकनीकों के माध्यम से उर्वरक और कच्चे माल के आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है।
- डिजिटल कृषि और एग्री स्टैक:** डिजिटल फसल सर्वेक्षण और किसान आईडी के माध्यम से उर्वरक वितरण प्रणाली में सुधार, सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण और संतुलित पोषण प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा उर्वरक आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण: “दीर्घकालिक उपायों से उर्वरक क्षेत्र की आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह घटेगा और यह भविष्य के वैश्विक झटकों के प्रति अधिक लचीला बनेगा। एग्री स्टैक इस दिशा में एक क्रांतिकारी डिजिटल मंच प्रदान करता है।” — डॉ. देवेश चतुर्वेदी

विषय 4: प्रकृति-स्मार्ट शहरों की रूपरेखा: प्रकृति-आधारित समाधानों (NBS) के इर्द-गिर्द शहरी योजना (DESIGNING NATURE-SMART CITIES: CENTRING URBAN PLANNING AROUND NATURE-BASED SOLUTIONS)

प्रकृति-आधारित समाधान (NBS), शहरी जलवायु लचीलापन, बाढ़ और ऊष्मीय तनाव (Heat Stress), नीली-हरी बुनियादी ढांचा (Blue-Green

और 24 राज्यों में 30 करोड़ से अधिक भूखंडों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण (Digital Crop Survey) किया गया है। एग्री स्टैक उर्वरक प्रबंधन प्रणाली को बदलने और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: उर्वरक रणनीतियां, तकनीकी विकल्प और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों, तकनीकी विकल्पों और उनके प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

Infrastructure), ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स, संजय गांधी नेशनल पार्क, हीट एक्शन प्लान, और RERA व नगर नियोजन में पारिस्थितिक नियम (लेखक: प्रो. हरिणी नागेंद्र, निदेशक, स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड Sustainability, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय)

प्रकृति-स्मार्ट शहर विजन: “चरम जलवायु परिवर्तन के युग में पारिस्थितिकी का महत्व समाप्त नहीं होता—यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रकृति-आधारित समाधान (NBS) शहरी जलवायु लचीलापन प्राप्त करने का एक प्रमुख मार्ग हैं।” — प्रो. हरिणी नागेंद्र

1. कार्यकारी सारांश एवं भारतीय शहरों में जलवायु संकट

जुलाई 2026 के ‘योजना’ अंक के चौथे आलेख ‘प्रकृति-स्मार्ट शहरों की रूपरेखा: प्रकृति-आधारित समाधानों (NBS) के इर्द-गिर्द शहरी योजना’ (Designing Nature-Smart Cities: Centring Urban Planning Around Nature-Based Solutions) में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी की निदेशक प्रोफेसर हरिणी नागेंद्र (एवं सह-लेखक अरविंद लक्ष्मिश और सीमा मुंडोली) ने विश्लेषण किया है कि कैसे भारतीय शहरों में बाढ़, लू (heatwaves), वायु प्रदूषण और जल संकट जैसी आपदाएं अब भविष्य की भविष्यवाणियां नहीं बल्कि रोजमर्रा की वास्तविकता बन चुकी हैं।

लेखक रेखांकित करते हैं कि पारंपरिक शहरी विकास ने प्रकृति को विकास में बाधक या ‘बंजर भूमि’ मानकर नष्ट किया है। हालांकि, झीलें, पेड़ और आर्द्रभूमि (wetlands) केवल सजावटी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचा (urban infrastructure) हैं जो बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, तापमान घटाते हैं और भूजल पुनर्भरण करते हैं।

2. प्रकृति-आधारित समाधान (NBS) और मौजूदा भारतीय उदाहरण

- NBS की परिभाषा:** आर्द्रभूमि बहाली, शहरी वन, मैंग्रोव संरक्षण, बायोस्वेल्स (bioswales), हरित गलियारे और नीली-हरी बुनियादी ढांचा (blue-green infrastructure) जलवायु अनुकूलन के शक्तिशाली उपकरण हैं।

- ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स: कोलकाता के लिए अपशिष्ट जल उपचार, मत्स्य पालन, बाढ़ अवशोषण और जैव विविधता का समर्थन करने वाला अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र।
- संजय गांधी नेशनल पार्क और मुंबई के मैग्रोव: सघन महानगर के भीतर तापमान को नियंत्रित करने और तटीय बाढ़ को रोकने वाला प्रमुख पारिस्थितिक बफर।

3. भूमि-विवश शहरों के लिए विकेंद्रीकृत NBS और असमानता

- अति-स्थानिक हस्तक्षेप: घनी आबादी वाले भारतीय शहरों में फ्लाइंगोवर के नीचे की जगह, सड़क के डिवाइडर, कैनाल के किनारे, रेलवे बफर, खाली सार्वजनिक भूमि, छतों और परिसरों में छोटे पैमाने पर NBS (पेड़-पौधे, रेन गार्डन) विकसित करना आवश्यक है।
- पर्यावरणीय असमानता: जलवायु जोखिम (लू, प्रदूषण, बाढ़) सभी पर समान रूप से असर नहीं डालते; अनधिकृत बस्तियों के निवासी, स्वच्छताकर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले और निर्माण श्रमिक इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

शहरी पारिस्थितिकी आयाम	पारंपरिक शहरी दृष्टिकोण	प्रकृति-आधारित समाधान (NBS)	दीर्घकालिक लाभ व प्रभाव
जल निकाय और आर्द्रभूमि	झीलों और वेटलैंड्स को कंक्रीट में बदलना और पाटना	झील बहाली, वेटलैंड संरक्षण और नीली-हरी बुनियादी ढांचा	बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जल सुरक्षा
शहरी ताप और हरियाली	पेड़ों को काटना और केवल आपातकालीन हीट एडवाइजरी जारी करना	शहरी वन, वृक्षारोपण और छायादार सार्वजनिक मार्ग	स्थानीय तापमान में कमी और बाहरी श्रमिकों को राहत
आपदा प्रबंधन	आपदा के बाद केवल राहत और प्रतिक्रिया (Reactive response)	प्रकृति-आधारित बफर, मैग्रोव सुरक्षा और पारगम्य सतहें	आपदा जोखिम में कमी और दीर्घकालिक जलवायु लचीलापन
संस्थागत योजना	विकास और पारिस्थितिकी को परस्पर विरोधी मानना	RERA, नगर नियोजन और नगरपालिका बजट में NBS को शामिल करना	समावेशी, न्यायसंगत और संधारणीय शहरी विकास

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु लचीलापन के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र I, II & III (शहरीकरण — समस्याएं और उपाय; पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट; आपदा प्रबंधन — जलवायु लचीलापन और प्रकृति-आधारित समाधान)

- प्रकृति-आधारित समाधान (NBS) और शहरी नियोजन: यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे भारतीय शहरों में बाढ़ और ऊष्मीय तनाव (Heat Stress) जैसी समस्याओं का समाधान केवल कंक्रीट के बुनियादी ढांचे से नहीं, बल्कि झीलों, वेटलैंड्स और शहरी वनों जैसे NBS को एकीकृत करके किया जा सकता है।
- पर्यावरणीय न्याय और समावेशिता: जलवायु जोखिमों के असमान वितरण को रेखांकित करते हुए, यह सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि शहरी हरियाली और पुनरुद्धार परियोजनाएं निम्न-आय वर्ग और हाशिए के समुदायों को बाहर न करें।

मुख्य परीक्षा प्रकृति-स्मार्ट शहर दृष्टिकोण: “भारतीय शहर अब पारिस्थितिकी और विकास को परस्पर विरोधी एजेंडे के रूप में मानने का जोखिम नहीं उठा सकते। जलवायु संकट ने दिखा दिया है कि पारिस्थितिक सोच के बिना बनाए गए शहर अधिक असमान, और संधारणीय रूप से महंगे हो जाते हैं।” — प्रो. हरिणी नागेंद्र

सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों को बाहर करना NBS की सफलता में बाधक है।

4. संस्थागत बदलाव, बजट और निजी क्षेत्र की भूमिका

- नगरपालिका बजट में सुधार: पारिस्थितिक पुनरुद्धार को वैकल्पिक खर्च (discretionary spending) के बजाय कोर शहरी बुनियादी ढांचे के रूप में देखना।
- RERA और नगर योजना की भूमिका: बड़े अपार्टमेंट परिसरों, वाणिज्यिक डेवलपर्स और टेक पार्कों को अपनी योजना में मूल पेड़ आवरण, पारगम्य सतहों और जल-संवेदनशील भूहश्य को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: प्रकृति-स्मार्ट शहर आयाम, चुनौतियां और समाधान

नीचे दी गई तालिका प्रकृति-आधारित समाधानों (NBS), शहरी चुनौतियों और नीतिगत सुधारों का विवरण प्रस्तुत करती है:

विषय 5: भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य: प्रगति, संभावनाएं और आगे की राह (INDIA'S HEALTH LANDSCAPE: PROGRESS, PROMISE, AND THE PATH AHEAD)

मातृ स्वास्थ्य (MMR सुधार), परिवार नियोजन और प्रजनन स्वायत्तता, सार्वभौमिक टीकाकरण (रोटावायरस वैक्सीन), बाल स्वास्थ्य और पोषण (स्टंटिंग में गिरावट), NCDs की चुनौती (मधुमेह और हृदय रोग), आयुषमान भारत PM-JAY, और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च में कमी (लेखक: प्रो. (डॉ.) प्रज्ञा शर्मा, कार्यकारी निदेशक, NHSRC)

स्वास्थ्य परिदृश्य विजन: “वह ज्ञान ही सत्य है जो [कष्टों से] मुक्ति दिलाता है। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य मिशन इसी प्राचीन दर्शन पर आधारित है, जहां स्वास्थ्य प्रणालियों का उद्देश्य नागरिकों को पीड़ा से मुक्त करना है।” — प्रो. (डॉ.) प्रज्ञा शर्मा

1. कार्यकारी सारांश एवं स्वास्थ्य डेटाबेस का विश्लेषण

जुलाई 2026 के ‘योजना’ अंक के पांचवें आलेख ‘भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य: प्रगति, संभावनाएं और आगे की राह’ (India's Health Landscape: Progress, Promise, and the Path Ahead) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) प्रज्ञा शर्मा ने विश्लेषण किया है कि कैसे हाल ही में जारी प्रमुख डेटाबेस—राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6), NSO 80वां दौर, SRS 2024, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते (NHA 2022-23)—भारत के स्वास्थ्य प्रणाली को परिणामों, उपयोग और व्यय के तीन लेंसों से देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं।

लेखक रेखांकित करते हैं कि यह डेटा केवल सांख्यिकीय रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जहां मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और वित्तीय सुरक्षा में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं, वहीं गैर-संचारी रोगों (NCDs) और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां एक नई चुनौती के रूप में उभरी हैं।

2. मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और टीकाकरण में प्रगति

- मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health):** प्रसव पूर्व देखभाल (ANC) और संस्थागत प्रसव 90% से अधिक हो गए हैं। NSO 80वें दौर के अनुसार संस्थागत प्रसव 96.2% हैं, और SRS-2024 के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) घटकर 87 पर आ गया है।
- परिवार नियोजन:** गर्भनिरोधक प्रचलन दर (CPR) बढ़कर 69.1% हो गई है, जबकि अप्रयुक्त आवश्यकता (unmet need) घटकर 8.5% रह गई है।
- सार्वभौमिक टीकाकरण:** 12-23 महीने के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज 87.1% हो गया है, जिसमें 95% टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से हुआ है। रोटावायरस वैक्सीन कवरेज दोगुने से अधिक होकर 85.4% हो गया है।

3. बाल स्वास्थ्य, पोषण और NCDs की उभरती चुनौती

- बाल स्वास्थ्य और पोषण:** SRS-2024 के अनुसार शिशु मृत्यु दर (IMR) घटकर 24 प्रति 1,000 लाइव जन्म हो गई है। NFHS-6 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टैटिंग (कम लंबाई) 35.5% से घटकर 29.3% हो गई है, हालांकि गंभीर वेस्टिंग (5.2%) अभी भी एक चिंता का विषय है।
- गैर-संचारी रोग (NCDs):** NSO 80वें दौर के अनुसार बीमारी की सूचना

स्वास्थ्य आयाम	प्रमुख डेटाबेस / पहल	परिचालन पैमाना व आंकड़े	सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव
मातृ और बाल स्वास्थ्य	NSO 80वां दौर, NFHS-6 और SRS-2024	संस्थागत प्रसव 96.2%; MMR घटकर 87; IMR घटकर 24	सुरक्षित मातृत्व और बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट
टीकाकरण और पोषण	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और NFHS-6	पूर्ण टीकाकरण 87.1%; रोटावायरस कवरेज 85.4%; स्टैटिंग 29.3%	संक्रामक रोगों पर नियंत्रण और बच्चों के पोषण में सुधार
वित्तीय सुरक्षा (OOPE)	आयुष्मान भारत PM-JAY और National Health Accounts	OOPE घटकर 39.4%; ₹1.52 लाख करोड़ की बचत	परिवारों को वित्तीय संकट से बचाना और स्वास्थ्य समानता
उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां	मधुमेह, हृदय रोग और मोटापा (NFHS-6 डेटा)	30.7% महिलाएं और 27.3% पुरुष अधिक वजन वाले	जीवनशैली रोगों (NCDs) का बढ़ता बोझ और निवारक देखभाल की आवश्यकता

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र के विकास और स्वास्थ्य नीतियों के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II (स्वास्थ्य, मानव संसाधन और सामाजिक क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दे — स्वास्थ्य संकेतक, वित्तीय सुरक्षा और NCDs की चुनौती)

- स्वास्थ्य परिणामों में सुधार:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे सरकारी पहलों (जैसे JSY, JSSK, और मिशन परिवार विकास) के कारण मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) में सुधार हुआ है।
- वित्तीय सुरक्षा और आयुष्मान भारत:** आयुष्मान भारत (PM-JAY) और जन औषधि जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE) में आई भारी गिरावट और वित्तीय सुरक्षा के प्रसार को रेखांकित करता है।

देने वाले व्यक्तियों का अनुपात (PPRA) लगभग दोगुना हो गया है। मधुमेह और हृदय रोगों के बोझ में तीन गुना वृद्धि हुई है।

- मोटापा और जीवनशैली:** NFHS-6 के अनुसार 30.7% महिलाएं और 27.3% पुरुष (15-49 वर्ष) अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, जो अल्ट्रा-प्रोपेस्ड फूड और sedentary जीवनशैली का परिणाम है।

4. वित्तीय सुरक्षा, आयुष्मान भारत और सार्वजनिक व्यय

- आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE) में कमी:** नागरिकों द्वारा सीधे जेब से किया जाने वाला स्वास्थ्य खर्च 62.6% (2014) से घटकर 39.4% (2025) रह गया है (NHA के अनुसार 64.2% से घटकर 43.4%)।
- आयुष्मान भारत (PM-JAY):** इस योजना ने परिवारों को ₹1.52 लाख करोड़ से अधिक के आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च से बचाया है, और सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवरेज में लगभग 19% की वृद्धि हुई है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च:** जीडीपी के हिस्से के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE) 1.15% से बढ़कर 1.43% हो गया है।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: स्वास्थ्य परिदृश्य, प्रगति और चुनौतियां

नीचे दी गई तालिका भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य के प्रमुख संकेतकों, प्रगति और उभरती चुनौतियों का विवरण प्रस्तुत करती है:

स्वास्थ्य आयाम	प्रमुख डेटाबेस / पहल	परिचालन पैमाना व आंकड़े	सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव
मातृ और बाल स्वास्थ्य	NSO 80वां दौर, NFHS-6 और SRS-2024	संस्थागत प्रसव 96.2%; MMR घटकर 87; IMR घटकर 24	सुरक्षित मातृत्व और बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट
टीकाकरण और पोषण	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और NFHS-6	पूर्ण टीकाकरण 87.1%; रोटावायरस कवरेज 85.4%; स्टैटिंग 29.3%	संक्रामक रोगों पर नियंत्रण और बच्चों के पोषण में सुधार
वित्तीय सुरक्षा (OOPE)	आयुष्मान भारत PM-JAY और National Health Accounts	OOPE घटकर 39.4%; ₹1.52 लाख करोड़ की बचत	परिवारों को वित्तीय संकट से बचाना और स्वास्थ्य समानता
उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां	मधुमेह, हृदय रोग और मोटापा (NFHS-6 डेटा)	30.7% महिलाएं और 27.3% पुरुष अधिक वजन वाले	जीवनशैली रोगों (NCDs) का बढ़ता बोझ और निवारक देखभाल की आवश्यकता

मुख्य परीक्षा स्वास्थ्य दृष्टिकोण: “स्वास्थ्य सेवा का धर्म यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक बीमारी और कष्टों से वंचित न रहे। आयुष्मान भारत और सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश इस प्राचीन भारतीय दर्शन का आधुनिक रूप में क्रियान्वयन है।” — प्रो. (डॉ.) प्रज्ञा शर्मा

विषय 6: जन-नवाचार: राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए मौन ज्ञान का उपयोग (PEOPLE'S INNOVATION: LEVERAGING TACIT KNOWLEDGE FOR NATIONAL SELF-RELIANCE)

मौन ज्ञान (Tacit Knowledge), जन-नवाचार (Grassroots Innovation), NIF (राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन), TKDL, पेटेंट और PPV&FR अधिनियम, प्रोजेक्ट कौडिन्य (सिलाई वाली नाव), और विक्रित भारत @ 2047 के लिए आत्मनिर्भरता (लेखक: डॉ. अरविंद सी. रानाडे, निदेशक, NIF)

जन-नवाचार विजन: “पारंपरिक और जमीनी स्तर के नवाचार केवल ऐतिहासिक रुचि के विषय नहीं हैं; वे भारत की आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की नींव हैं। साधारण नागरिकों की आविष्कारक क्षमता विकसित भारत 2047 की आधारशिला है।” — डॉ. अरविंद सी. रानाडे

1. कार्यकारी सारांश एवं जन-नवाचार (Grassroots Innovation) की अवधारणा

जुलाई 2026 के ‘योजना’ अंक के छठे आलेख ‘जन-नवाचार: राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए मौन ज्ञान का उपयोग’ (People’s Innovation: Leveraging Tacit Knowledge for National Self-Reliance) में राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (NIF) के निदेशक डॉ. अरविंद सी. रानाडे (एवं सह-लेखक डॉ. विवेक कुमार) ने विश्लेषण किया है कि कैसे औपचारिक अनुसंधान और विकास (R&D) प्रयोगशालाओं के बाहर, आम नागरिक अपनी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, मौन ज्ञान (tacit knowledge) और स्थानीय तात्कालिकता के आधार पर अनूठे नवाचारों को जन्म देते हैं।

लेखक रेखांकित करते हैं कि भारत जैसी प्राचीन और विविधतापूर्ण सभ्यता (जिसमें 4,635 समुदाय, 780 भाषाएं और 730+ जनजातीय समूह शामिल हैं) पीढ़ियों से संचित पारंपरिक ज्ञान का एक विशाल भंडार रखती है। प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत @ 2047’ के विजन के तहत आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta) और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में ये जन-नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. मौन ज्ञान और विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र

- भारत की विशाल जनसांख्यिकी और 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्रों (मेगाडाइवर्स देश) ने कृषि, चिकित्सा, शिल्प और सामग्री विज्ञान में स्थानीय रूप से अनुकूलित तकनीकों को जन्म दिया है।
- ऐतिहासिक उदाहरण और प्रोजेक्ट कौडिन्य: इतिहास में ‘होर्टस मलाबारीकस’ (Hortus Malabaricus) जैसे संकलन इस बात का प्रमाण हैं कि कैसे पारंपरिक ज्ञान (जैसे एड्वावा चिकित्सक इट्टी अचूथन का योगदान) यूरोपीय वानिकी का आधार बना। हाल ही में जनवरी 2026 में प्राचीन केरल परंपरा पर आधारित ‘प्रोजेक्ट कौडिन्य’ के तहत बिना लोहे की

कील के, केवल नारियल रसी और प्राकृतिक रेजिन से बनी महासागरीय नौका ने पोरबंदर से मस्कट (ओमान) तक 18 दिन की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की।

3. संस्थागत वास्तुकला और बौद्धिक संपदा सुरक्षा

- ज्ञान की अदृश्यता और निष्कर्षण की चुनौती:** मौखिक परंपराओं में मौजूद ज्ञान मानक कानूनी प्रणालियों या पेटेंट प्रणालियों में आसानी से दर्ज नहीं होता, जिससे बाहरी अभिनेताओं द्वारा बिना श्रेय या मुआवजे के इसे हथियाने (biopiracy) का जोखिम रहता है।
- संस्थागत सुरक्षा उपाय:** भारत ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL), नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF), प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स (PPV&FR) अधिनियम, और पेटेंट अधिनियम की धारा 3(p) के माध्यम से इस ज्ञान को कानूनी संरक्षण प्रदान किया है।

4. NIF की भूमिका और उपलब्धियां

- स्काउटिंग और दस्तावेजीकरण:** NIF ने 730+ जिलों से 3.75 लाख से अधिक तकनीकी विचारों, नवाचारों और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया है।
- पेटेंट और पंजीकरण:** NIF के माध्यम से 1,478 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं (जिनमें 725 पेटेंट मंजूर हुए हैं), तथा किसानों की विकसित 95 पादप किस्मों में से 50 पंजीकृत की गई हैं।
- उद्यमशीलता और वित्तीय सहायता:** SIDBI के साथ माइक्रोज वेंचर इनोवेशन फंड (MVIF) के माध्यम से 238 नवाचार-आधारित उद्यमों को जोखिम पूंजी (risk capital) दी गई है, तथा कई नवप्रवर्तकों को राष्ट्रीय पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: जन-नवाचार आयाम, संस्थागत समर्थन और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका जन-नवाचार के प्रमुख घटकों, NIF की भूमिका और उनके राष्ट्रीय प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

नवाचार आयाम	मुख्य फोकस व संस्थागत तंत्र	परिचालन पैमाना व मैट्रिक्स	आर्थिक व सामाजिक प्रभाव
मौन ज्ञान और विविधता	समुदाय-आधारित मौखिक परंपराएं और जैव-सांस्कृतिक विरासत	4,635 समुदाय और 780+ भाषाएं आधारित विविधता	स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल व्यावहारिक समाधानों का सृजन
स्काउटिंग और दस्तावेजीकरण	NIF (राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन) और पूर्व सूचित सहमति (PIC)	730+ जिलों से 3.75 लाख+ विचारों और नवाचारों का डेटाबेस	अदृश्य ज्ञान को औपचारिक रिकॉर्ड और सुलभ परिसंपत्ति में बदलना
बौद्धिक संपदा और पेटेंट	पेटेंट अधिनियम की धारा 3(p), TKDL और PPV&FR अधिनियम	1,478+ पेटेंट आवेदन (725 स्वीकृत) और 50 पादप किस्में पंजीकृत	पारंपरिक ज्ञान धारकों के अधिकारों की रक्षा और शोषण की रोकथाम
उद्यमिता और प्रसार	माइक्रोज वेंचर इनोवेशन फंड (MVIF) और DPIIT स्टार्टअप मान्यता	238 उद्यमों को जोखिम पूंजी सहायता और राष्ट्रीय पद्म सम्मान	स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को मजबूती

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — स्वदेशी तकनीक और IPR; आर्थिक विकास — समावेशी विकास, नवाचार और स्टार्टअप)

- जन-नवाचार (Grassroots Innovation) और आत्मनिर्भरता:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे पारंपरिक प्रयोगशालाओं के बाहर आम नागरिकों और समुदायों द्वारा विकसित मौन ज्ञान (tacit knowledge) भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और विकसित भारत 2047 के विजन को मजबूत कर रहा है।
- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और पारंपरिक ज्ञान:** पारंपरिक ज्ञान की चोरी (biopiracy) को रोकने के लिए TKDL, NIF और पेटेंट कानूनों जैसी संस्थागत प्रणालियों की भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा जन-नवाचार दृष्टिकोण: “देश की नवाचार क्षमता का एक बड़ा हिस्सा विकेंद्रीकृत, जमीनी स्तर और पारंपरिक ज्ञान-आधारित नवाचारों में निहित है। सामान्य नागरिकों की आविष्कारक क्षमता विकसित भारत 2047 की आधारशिला है।” — डॉ. अरविंद सी. रानाडे

विषय 7: भविष्य के लिए तैयार भारत के लिए शिक्षा और कौशल (EDUCATION AND SKILLS FOR A FUTURE-READY INDIA)

जनसांख्यिकी लाभांश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, बजट आवंटन 2026-27 (₹1,39,289.48 करोड़), ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ स्थायी समिति, विश्वविद्यालय टाउनशिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और कौशल विकास (लेखक: सुनील कुमार बत्ता, वरिष्ठ पत्रकार)

शिक्षा और कौशल विजन: “हम देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार आधुनिक बना रहे हैं। प्रतिभा (Talent), स्वभाव (Temperament) और प्रौद्योगिकी (Technology) की त्रिमूर्ति भारत के भविष्य को बदल देगी।” — नरेंद्र मोदी

1. कार्यकारी सारांश एवं मानव पूंजी का महत्व

जुलाई 2026 के ‘योजना’ अंक के सातवें आलेख ‘भविष्य के लिए तैयार भारत के लिए शिक्षा और कौशल’ (Education and Skills for a Future-Ready India) में वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार बत्ता ने विश्लेषण किया है कि कैसे विकसित भारत @ 2047 के विजन को प्राप्त करने में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विस्तार के साथ-साथ ‘मानव पूंजी’ (human capital) सबसे निर्णायक कारक होगी।

लेखक रेखांकित करते हैं कि भारत की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और 2055 तक यह दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में बना रहेगा। जहां कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं वृद्ध होती आबादी से जूझ रही हैं, वहीं भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव पूंजी भंडार बनने का अनूठा अवसर है। हालांकि, यह जनसांख्यिकी लाभांश तभी प्रभावी होगा जब युवा शिक्षित, कुशल, रोजगार योग्य और उत्पादक हों।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और सार्वजनिक निवेश

- NEP 2020 का परिवर्तनकारी फ्रेमवर्क: बहुविषयक शिक्षा (multidisciplinary learning), डिजिटल शिक्षा, आलोचनात्मक

सोच, पाठ्यचर्या लचीलापन, व्यावसायिक एकीकरण, और मातृभाषा आधारित बुनियादी शिक्षा पर विशेष जोर।

- बढ़ता बजट आवंटन:** केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय को ₹1,39,289.48 करोड़ (पिछले वर्ष से 8.27% अधिक) आवंटित किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों में शिक्षा क्षेत्र का आवंटन लगभग 50% बढ़ा है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा:** स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को रिकॉर्ड ₹83,562 करोड़, तथा उच्च शिक्षा को ₹55,727.22 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो उन्नत कौशल और अनुसंधान पर जोर को दर्शाता है।

3. नीतिगत पहलें: स्थायी समिति और विश्वविद्यालय टाउनशिप

- ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ स्थायी समिति:** सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का मुख्य चालक बनाने, वैश्विक शेयर को 2047 तक 10% तक पहुंचाने, और AI के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए नीति आयोग के CEO की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति का गठन।
- विश्वविद्यालय टाउनशिप (University Townships):** प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास 5 आधुनिक विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करने में राज्यों को सहायता, जहां बहु-विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र और कौशल केंद्र एक साथ होंगे।

4. भविष्य के लिए तैयार कौशल और रोजगार

- तकनीकी और मानवीय कौशल:** कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, AI, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, और हरित ऊर्जा प्रणालियों के साथ-साथ रचनात्मकता, समस्या-समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता (adaptability) का समन्वय।
- कौशल भारत मिशन (Skill India Mission) और PMKVY:** लाखों युवाओं को स्वास्थ्य सेवा, IT सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना।
- AI का लोकतंत्रीकरण:** फरवरी 2026 में आयोजित ‘इंडिया AI इंपैक्ट समिट’ के माध्यम से AI को ग्लोबल साउथ के लिए समावेशन और सशक्तिकरण का साधन बनाना।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: शिक्षा, कौशल और नीतिगत प्रभाव

नीचे दी गई तालिका शिक्षा सुधारों, वित्तीय निवेश और भविष्य के कार्यबल की तैयारी का विवरण प्रस्तुत करती है:

शिक्षा व कौशल आयाम	मुख्य नीतिगत पहल	वित्तीय निवेश व पैमाना	दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव
शैक्षिक सुधार (NEP 2020)	मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा, IKS समावेशन और मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा	स्कूली शिक्षा बजट रिकॉर्ड ₹83,562 करोड़	छात्रों में आलोचनात्मक सोच और अनुभवात्मक लर्निंग का विकास
सार्वजनिक निवेश	केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा के लिए कुल परिव्यय	₹1,39,289.48 करोड़ (पिछले वर्ष से 8.27% की वृद्धि)	बुनियादी ढांचे, डिजिटल लर्निंग और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण
रोजगार और उद्यम समिति	नीति आयोग CEO की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन	सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना और वैश्विक शेयर को 10% तक ले जाना	आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि
भविष्य के कौशल (AI & Skills)	कौशल भारत मिशन, PMKVY और इंडिया AI इंपैक्ट समिट	करोड़ों युवाओं को उन्नत तकनीकों और कोडिंग में प्रशिक्षण	वैश्विक कार्यबल गतिशीलता और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख मानव संसाधन, शिक्षा नीति और कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & III (मानव संसाधन — शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे; आर्थिक विकास — रोजगार सृजन और ज्ञान अर्थव्यवस्था)

- **जनसांख्यिकी लाभांश और शिक्षा:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे भारत अपने विशाल युवा कार्यबल को (जो 2055 तक युवा बना रहेगा) NEP 2020 और बढ़ते बजट निवेश के माध्यम से एक कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल में बदल सकता है।
- **एआई और भविष्य के कौशल:** उद्योग-अकादमिक साझेदारी, विश्वविद्यालय टाउनशिप और स्थायी समितियों के माध्यम से शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के रणनीतिक प्रयासों को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा शिक्षा और कौशल दृष्टिकोण: “विकसित भारत @ 2047 का विजन केवल एक आर्थिक आकांक्षा नहीं है; यह मौलिक रूप से एक मानव विकास मिशन है। भारत का भविष्य उसकी आबादी के आकार से नहीं, बल्कि उसके लोगों की गुणवत्ता, क्षमता और रचनात्मकता से तय होगा।” — सुनील कुमार बला

विषय 8: वीरता से मूल्यों की ओर: प्रोजेक्ट वीर गाथा — विरासत से नागरिक चेतना तक (VALOUR TO VALUES: PROJECT VEER GATHA — FROM LEGACY TO CIVIC CONSCIOUSNESS)

प्रोजेक्ट वीर गाथा (संस्करण 5.0), राष्ट्र प्रथम (Rashtra Pratham), गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल (GAP), अनुभवात्मक शिक्षा (Experiential Pedagogy), ‘सुपर 100’ राष्ट्रीय विजेता, स्कूलों में ‘वीर गाथा कॉर्नर’, और NEP 2020 व GCED के साथ संरेखण (लेखक: डॉ. शुभांकर मिश्रा, संयुक्त निदेशक, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय)

वीर गाथा विजन: “विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परन्तु यों मरो कि याद जो करे सभी... शौर्य केवल उत्तरजीविता नहीं है; यह सामूहिक स्मृति पर छोड़ी गई एक चिरस्थायी छाप है।” — मैथिलीशरण गुप्त / डॉ. शुभांकर मिश्रा

1. कार्यकारी सारांश एवं प्रोजेक्ट वीर गाथा की अवधारणा

जुलाई 2026 के ‘योजना’ अंक के आठवें आलेख ‘वीरता से मूल्यों की ओर: प्रोजेक्ट वीर गाथा — विरासत से नागरिक चेतना तक’ (Valour to Values: Project Veer Gatha — From Legacy to Civic Consciousness) में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. शुभांकर मिश्रा ने विश्लेषण किया है कि कैसे 2021 में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया ‘प्रोजेक्ट वीर गाथा’ वीरता और बलिदान की कहानियों को स्कूली छात्रों के लिए मूल्यों की एक संरचित शिक्षा (pedagogy of values) में बदल रहा है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि प्रोजेक्ट वीर गाथा केवल एक प्रतियोगिता या मिशन नहीं है, बल्कि यह इस बात की याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि नागरिकों द्वारा सम्मानित साहस और संजोए गए मूल्यों से जीवंत रहते हैं। यह पहल देशभक्ति को केवल युद्धक्षेत्र तक सीमित न रखकर कक्षाओं में नैतिक समझ और नागरिक चेतना के रूप में गढ़ती है।

2. मूल्य आधारित शिक्षा और राष्ट्रीय भागीदारी (Scale and Growth)

- **सहभागी विकास (24x वृद्धि):** वीर गाथा के पहले संस्करण (2021-22) में 8 लाख छात्रों की भागीदारी से बढ़कर ‘वीर गाथा 5.0’ (2025-26) में यह संख्या 1.92 करोड़ छात्रों तक पहुंच गई है।
- **कक्षा 3 से 12 तक पहुंच:** देश भर के स्कूलों में कक्षा 3 से 12 तक के छात्र निबंध, कविता, कहानी, चित्रकला और डिजिटल अभिव्यक्ति सहित 7 विभिन्न श्रेणियों में भाग लेते हैं।
- **सुपर 100 (Super 100):** बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया (स्कूल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर) के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 100 शीर्ष राष्ट्रीय विजेताओं को ‘सुपर 100’ के रूप में सम्मानित किया जाता है।

3. शिक्षाशास्त्र (Pedagogy) और वैचारिक ढांचा

- **NEP 2020 के साथ संरेखण:** यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस दृष्टिकोण से जुड़ी है जो तार्किक, संवेदनशील, रचनात्मक और नैतिक रूप से ग्राउंडेड व्यक्तियों के निर्माण की परिकल्पना करती है।
- **वैश्विक शैक्षिक ढांचा:** यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH), सतत विकास के लिए शिक्षा (ESD 2030), और वैश्विक नागरिकता शिक्षा (GCED) के सिद्धांतों के साथ संरेखित है, जो छात्रों को कर्तव्य, सेवा और न्याय जैसे नागरिक मूल्यों के सक्रिय निर्माता के रूप में स्थापित करता है।
- **ऐतिहासिक निरंतरता:** समकालीन गैलेंट्री पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, कलिंग नरेश खारवेल, तथा मगध और चोल साम्राज्यों के ऐतिहासिक योद्धाओं की कहानियों को शामिल करके ऐतिहासिक और सभ्यतागत चेतना को गहरा किया गया है।

4. संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र और ‘वीर गाथा कॉर्नर’

- **डिजिटल और भौतिक मंच:** MyGov पोर्टल, CBSE, राज्य शिक्षा विभागों और नोडल अधिकारियों के समन्वय से संचालित यह कार्यक्रम ‘कभी भी, कहीं भी’ (Janiye Kabhi bhi, Kahin bhi) सीखने के अनुभव प्रदान करता है।
- **स्कूलों में ‘वीर गाथा कॉर्नर’:** देश भर के स्कूलों में विशेष ‘वीर गाथा कॉर्नर’ स्थापित किए गए हैं, जो छात्रों की रचनात्मकता, कलाकृतियों और वीरता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाले जीवंत संस्थानिक स्मृति केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: वीर गाथा आयाम, पैमाना और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका प्रोजेक्ट वीर गाथा के प्रमुख घटकों, भागीदारी के पैमाने और नागरिक चेतना पर प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

वीर गाथा आयाम	मुख्य फोकस व मंत्रालय	परिचालन पैमाना व मेट्रिक्स	नागरिक और शैक्षिक प्रभाव
संस्थागत सहभागिता	रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल (GAP पोर्टल)	8 लाख (2021) से बढ़कर 1.92 करोड़ छात्र (वीर गाथा 5.0)	देशव्यापी छल भागीदारी और राष्ट्र प्रथम (Rashtra Pratham) की भावना.
मूल्य आधारित शिक्षा	NEP 2020 और IKS आधारित अनुभवात्मक शिक्षा (Experiential Pedagogy)	कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए 7 रचनात्मक श्रेणियां	रटने की प्रवृत्ति से हटकर आलोचनात्मक सोच और नैतिक मूल्यों का विकास.
विरासत और प्रतीक	ऐतिहासिक योद्धाओं और गैलेंट्री पुरस्कार विजेताओं की जीवनगाथाएं	स्कूलों में 'वीर गाथा कॉर्नर' की स्थापना और संवाद सत्र	जीवित संस्थागत स्मृति और वीरता की कहानियों का अंतर-पीढ़ीगत संचरण.
मूल्यांकन और पुरस्कार	बहु-स्तरीय चयन प्रक्रिया (स्कूल से राष्ट्रीय स्तर तक)	100 उत्कृष्ट राष्ट्रीय विजेताओं का चयन ('सुपर 100')	युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, उत्तरदायित्व और नागरिक चेतना को बढ़ावा.

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पलों के लिए यह आलेख शिक्षा नीति, नागरिक चेतना और राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & IV (शासन व्यवस्था — शिक्षा नीतियां और मूल्य आधारित शिक्षा; नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि — देशभक्ति, कर्तव्य बोध और नागरिक उत्तरदायित्व)

- वीर गाथा और नागरिक चेतना:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे प्रोजेक्ट वीर गाथा जैसी पहलें स्कूली शिक्षा में वीरता, बलिदान और संवैधानिक मूल्यों को समाहित करके छात्रों को जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक (Responsible Citizens) बनाती हैं.
- अनुभवात्मक शिक्षा और राष्ट्र निर्माण:** पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर कला, डिजिटल अभिव्यक्ति और पुरस्कार विजेताओं के साथ सीधे संवाद के माध्यम से 'राष्ट्र प्रथम' (Rashtra Pratham) के भाव को सुदृढ़ करने के शैक्षणिक महत्व को रेखांकित करता है.

मुख्य परीक्षा वीर गाथा दृष्टिकोण: "वीर गाथा केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक नागरिक शिक्षण आंदोलन है जो इतिहास, रचनात्मकता और पहचान को राष्ट्रीय चेतना के एक जीवंत ढांचे में पिरोता है। राष्ट्र प्रथम (Rashtra Pratham) ही इसका मूल मंत्र है।" — डॉ. शुभांकर मिश्रा

विषय 9: आंतरिक संतुलन, बाहरी दीप्ति: सौंदर्य और समग्र स्वास्थ्य (INNER BALANCE, OUTER RADIANCE: WELLNESS AND HOLISTIC BEAUTY)

समग्र स्वास्थ्य (Holistic Well-being), योग और प्राणायाम, त्वचा और बालों की जीवन शक्ति, माइंडफुलनेस (सचेतनता), स्वस्थ उम्र बढ़ना (Healthy Ageing), और मुद्रा व आत्मविश्वास (लेखक: शहनाज हुसैन, अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य विशेषज्ञ एवं पद्म पुरस्कार विजेता)

वेलनेस विजन: "ऐसी दुनिया में जहां बाहरी समाधानों का बोलबाला है, योग हमें याद दिलाता है कि स्थायी दीप्ति भीतर से शुरू होती है। योग को जीवनशैली के रूप में अपनाकर, व्यक्ति जीवन शक्ति और शांति पैदा कर सकता है।" — शहनाज हुसैन

1. कार्यकारी सारांश एवं समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा

जुलाई 2026 के 'योजना' अंक के नौवें आलेख 'आंतरिक संतुलन, बाहरी दीप्ति: सौंदर्य और समग्र स्वास्थ्य' (Inner Balance, Outer Radiance: Wellness and Holistic Beauty) में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य

विशेषज्ञ और पद्म पुरस्कार विजेता शहनाज हुसैन ने विश्लेषण किया है कि कैसे वास्तविक कल्याण (well-being) केवल बाहरी दिखावे से परे, शरीर, मन और भावनाओं के बीच संतुलन पर आधारित होता है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि प्राचीन भारतीय परंपराएं हमेशा से शारीरिक स्वास्थ्य और आंतरिक कल्याण के बीच सामंजस्य पर जोर देती रही हैं। आधुनिक जीवनशैली में तनाव, निष्क्रियता और पर्यावरणीय कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ऐसे में योग और माइंडफुलनेस शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति का एक सरल और सुलभ मार्ग प्रदान करते हैं।

2. योग, त्वचा और बालों की जीवन शक्ति

- त्वचा पर प्रभाव:** शरीर का सबसे बड़ा अंग होने के नाते त्वचा पोषण, जलयोजन, नींद और तनाव जैसे कारकों पर प्रतिक्रिया करती है। योग रक्त संचार (blood circulation) को बेहतर बनाकर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जिससे त्वचा प्राकृतिक रूप से ऊर्जावान और स्वस्थ दिखती है।
- बालों का स्वास्थ्य:** आहार, तनाव स्तर और नींद की आदतें बालों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। योग और ध्यान से तनाव में कमी आती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ बालों की देखभाल में सहायक है।

3. प्राणायाम, माइंडफुलनेस और स्वस्थ उम्र बढ़ना

- प्राणायाम और श्वास नियमन:** श्वास को नियंत्रित करने की योगिक तकनीक (प्राणायाम) तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देती है।
- माइंडफुलनेस (सचेतनता):** वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है। तनाव मुँहासे (acne) और त्वचा की संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, जिसे माइंडफुलनेस से नियंत्रित किया जा सकता है।
- स्वस्थ उम्र बढ़ना (Healthy Ageing):** उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। योग रीढ़ की हड्डी के संरक्षण, लचीलेपन और मांसपेशियों को मजबूत करके शरीर को सक्रिय रखता है।

4. मुद्रा, आत्मविश्वास और आंतरिक दीप्ति

- शारीरिक मुद्रा और आत्मविश्वास:** वास्तविक सौंदर्य में अच्छी मुद्रा (posture), आत्मविश्वास और शालीनता शामिल हैं। योग शरीर को मजबूत करने के साथ संतुलन और अनुग्रह विकसित करता है।
- आंतरिक सौंदर्य:** नियमित योग अभ्यास से अनुशासन, शांति और आत्मविश्वास झलकता है, जो किसी भी बाहरी कॉस्मेटिक उपचार से अधिक प्रभावी होता है।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: वेलनेस आयाम, अभ्यास और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका समग्र स्वास्थ्य के प्रमुख घटकों, योगिक अभ्यासों और उनके प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

वेलनेस आयाम	प्रमुख योगिक तकनीक / अभ्यास	शारीरिक व मानसिक प्रक्रिया	दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव
त्वचा और बाल स्वास्थ्य	शारीरिक आसन और रक्त संचार बढ़ाने वाले व्यायाम	ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में सुधार	प्राकृतिक दीप्ति, स्वस्थ त्वचा और मजबूत बाल
प्राणायाम व श्वास	सचेत श्वास नियमन और ध्यान तकनीकें	तंत्रिका तंत्र को शांत करना और तनाव कम करना	भावनात्मक संतुलन, बेहतर नींद और मानसिक स्पष्टता
स्वस्थ उम्र बढ़ना	लचीलेपन और रीढ़ की हड्डी के संरेखण वाले आसन	जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखना और मांसपेशियों को मजबूती	उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक सक्रियता और ऊर्जावान अनुभव
मुद्रा और व्यक्तित्व	शरीर जागरूकता और संतुलन आधारित योग अभ्यास	आत्मविश्वासपूर्ण शारीरिक मुद्रा और शालीनता	आकर्षक व्यक्तित्व और आंतरिक अनुशासन का प्रकटीकरण

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख स्वास्थ्य, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है: सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & IV (स्वास्थ्य, कल्याणकारी नीतियां और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का वैश्विक प्रसार; नैतिकता — मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और जीवनशैली)

- योग और निवारक स्वास्थ्य (Preventive Healthcare): यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे प्राचीन भारतीय योग परंपरा और प्राणायाम

आज की तनावपूर्ण जीवनशैली में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य का एक सशक्त माध्यम बन चुके हैं।

- समग्र कल्याण (Holistic Well-being): बाहरी सौंदर्य और कृत्रिम उत्पादों से आगे बढ़कर आंतरिक संतुलन, मानसिक शांति और जीवनशैली में सुधार के माध्यम से सतत कल्याण को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा वेलनेस दृष्टिकोण: “ऐसी दुनिया में जहां बाहरी समाधानों का बोलबाला है, योग हमें याद दिलाता है कि स्थायी दीप्ति भीतर से शुरू होती है। योग को जीवनशैली के रूप में अपनाकर व्यक्ति जीवन शक्ति और शांति प्राप्त कर सकता है।” — शहनाज हुसैन